

ग्रामीण बस्तियों के बदलते स्वरूप का एक भू-नगरीकरण अध्ययन देहरादून जिले के विशेष सन्दर्भ में

शिल्पी

डॉ. चंद्र मोहन राजोरिया

भूगोल विभाग,

भगवंत विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान

DECLARATION: I AS AN AUTHOR OF THIS PAPER /ARTICLE, HERE BY DECLARE THAT THE PAPER SUBMITTED BY ME FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL IS COMPLETELY MY OWN GENUINE PAPER. IF ANY ISSUE REGARDING COPYRIGHT/PATENT/OTHER REAL AUTHOR ARISES, THE PUBLISHER WILL NOT BE LEGALLY RESPONSIBLE. IF ANY OF SUCH MATTERS OCCUR PUBLISHER MAY REMOVE MY CONTENT FROM THE JOURNAL WEBSITE. FOR THE REASON OF CONTENT AMENDMENT/OR ANY TECHNICAL ISSUE WITH NO VISIBILITY ON WEBSITE /UPDATES, I HAVE RESUBMITTED THIS PAPER FOR THE PUBLICATION.FOR ANY PUBLICATION MATTERS OR ANY INFORMATION INTENTIONALLY HIDDEN BY ME OR OTHERWISE, I SHALL BE LEGALLY RESPONSIBLE. (COMPLETE DECLARATION OF THE AUTHOR AT THE LAST PAGE OF THIS PAPER/ARTICLE)

सारांश

देहरादून जिला, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरणीय महत्व के लिए प्रसिद्ध है, वर्तमान में भू-नगरीकरण की तीव्र प्रक्रिया का सामना कर रहा है। यह शोधपत्र देहरादून जिले की ग्रामीण बस्तियों के बदलते स्वरूप और इसके भू-नगरीकरण के प्रभावों का विश्लेषण करता है। अध्ययन में 1991 से 2021 तक के जनसंख्या, भूमि उपयोग, और पर्यावरणीय परिवर्तनों का स्थानिक और सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द: भू-नगरीकरण, ग्रामीण बस्तियाँ, देहरादून, भूमि उपयोग परिवर्तन, जी आई एस

1.1 परिचय

उत्तराखण्ड राज्य की राजधानी देहरादून, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है, बीते तीन दशकों में शहरीकरण के तीव्र गति का साक्षी बनी है। यह क्षेत्र अपने रणनीतिक भौगोलिक स्थान, अनुकूल जलवायु, और सामाजिक-आर्थिक अवसरों के कारण तेजी से विकासशील नगरों में से एक है। देहरादून के शहरी क्षेत्र का यह विस्तार केवल जनसंख्या वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भूमि उपयोग के पैटर्न, पर्यावरणीय संरचना, और सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को भी प्रभावित कर रहा है।

1990 के दशक में, देहरादून मुख्य रूप से एक शांत पहाड़ी नगर था। लेकिन राज्य गठन (2000) के बाद यह तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। देहरादून में शहरीकरण की इस तीव्र गति के पीछे कई कारक हैं, जिनमें बढ़ता प्रवासन, औद्योगिक विकास, और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना प्रमुख हैं। यह शहर उत्तर भारत के प्रमुख महानगरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे यहां व्यवसाय और निवास के अवसरों में वृद्धि हुई है।

शहरीकरण के इस अभूतपूर्व विकास के साथ ही पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। कृषि भूमि और वनों का शहरी बस्तियों में परिवर्तन, जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव, और वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण बन गए हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी बुनियादी ढांचे की मांग और यातायात की समस्याओं ने शहर के प्रशासन के लिए नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। ग्रामीण बस्तियाँ लंबे समय से भारतीय समाज की रीढ़ रही हैं। इन बस्तियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, और आर्थिक प्रक्रियाएँ समय के साथ विकसित होती रही हैं। हाल के दशकों में, शहरीकरण की प्रक्रिया ने ग्रामीण बस्तियों के स्वरूप को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। देहरादून जिला, जो उत्तराखण्ड राज्य का प्रमुख क्षेत्र है, इस भू-नगरीकरण की प्रक्रिया के स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

भू-नगरीकरण की परिभाषा और संदर्भ

भू-नगरीकरण (ळमवनतइंद्रप्रंजपवद) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप शहरी विशेषताओं को अपनाता है। इसमें न केवल भौतिक संरचनाओं का परिवर्तन शामिल होता है, जैसे कि भवनों और सड़कों का निर्माण, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने में भी बदलाव देखने को मिलता है। यह प्रक्रिया विकास के विभिन्न आयामों को समेटे हुए होती है, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विस्तार, कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था से सेवा और औद्योगिक क्षेत्र की ओर परिवर्तन, तथा जीवन शैली और सांस्कृतिक पैटर्न में बदलाव।

देहरादून जिले का विशेष संदर्भ

देहरादून, हिमालय की तलहटी में स्थित, एक समय में शांत और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ग्रामीण क्षेत्र था। हाल के वर्षों में, यह जिला शहरी विस्तार और आर्थिक विकास का केंद्र बन गया है। यहाँ की ग्रामीण बस्तियाँ धीरे-धीरे आधुनिक शहरी सुविधाओं और अधोसंरचनाओं से जुड़ रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, और यातायात के विकास ने इस जिले की ग्रामीण बस्तियों को शहरी प्रभावों के तहत ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1.2 अध्ययन की आवश्यकता और महत्व

ग्रामीण बस्तियों के बदलते स्वरूप का अध्ययन न केवल सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि यह क्षेत्रीय योजना, पर्यावरणीय प्रबंधन, और सामुदायिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। देहरादून जिले में बढ़ते शहरीकरण के परिणामस्वरूप पर्यावरणीय चुनौतियाँ, जैसे कि जल संसाधनों का दोहन, वनों की कटाई, और भूमि उपयोग परिवर्तन, गंभीर चिंताओं के रूप में उभरी हैं।

इस अध्ययन का उद्देश्य इन परिवर्तनों की पहचान करना, उनकी प्रकृति का विश्लेषण करना, और उनके संभावित प्रभावों को समझना है। यह शोध देहरादून की ग्रामीण बस्तियों के भू-नगरीकरण के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास और योजना निर्माण में योगदान देगा।

1.3 उद्देश्य

- देहरादून जिले की ग्रामीण बस्तियों के भू-नगरीकरण पैटर्न का विश्लेषण।
- भू-नगरीकरण के प्रमुख कारणों और इसके प्रभावों का अध्ययन।
- ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच के संबंधों की पहचान।

1.4 कार्यप्रणाली

- डेटा स्रोत:
 - भारत की जनगणना (1991–2021)
 - उपग्रह इमेजरी (लैंडसैट)
 - क्षेत्रीय सर्वेक्षण

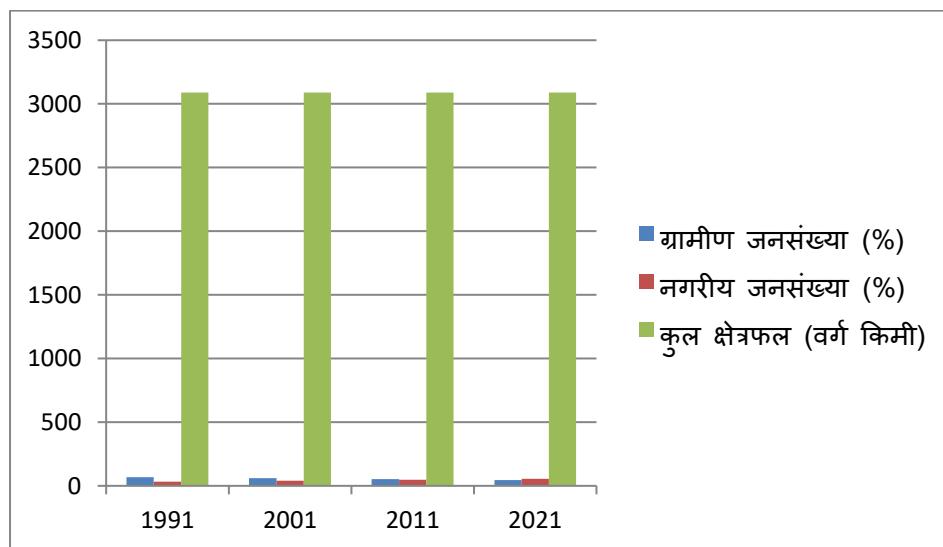
- विश्लेषण उपकरण: GIS रिमोट सेंसिंग, सांख्यिकीय तकनीकें

1.5 परिणाम और चर्चा

1.5.1 ग्रामीण बस्तियों का स्थानिक वितरण

तालिका 1 में देहरादून जिले की ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के क्षेत्रफल और जनसंख्या का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

वर्ष	ग्रामीण जनसंख्या (%)	नगरीय जनसंख्या (%)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
1991	68.5	31.5	3088
2001	60.2	39.8	3088
2011	52.7	47.3	3088
2021	45.1	54.9	3088

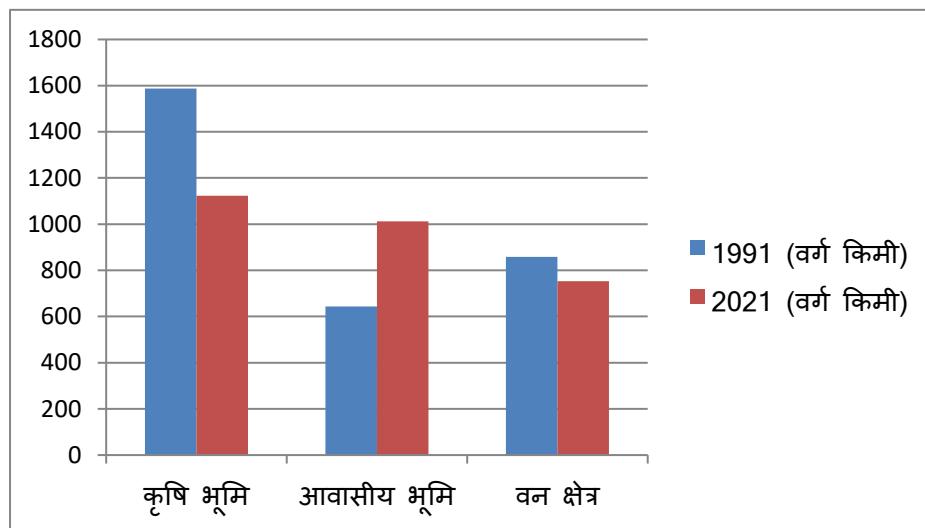


बार ग्राफ 1: ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत (1991–2021)

1.5.2 भूमि उपयोग परिवर्तन

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का नगरीय आवासीय और औद्योगिक उपयोग में तेजी से परिवर्तन हुआ है।

भूमि उपयोग का प्रकार	1991 (वर्ग किमी)	2021 (वर्ग किमी)
कृषि भूमि	1587	1123
आवासीय भूमि	643	1012
वन क्षेत्र	858	753



बार ग्राफ 2: भूमि उपयोग में बदलाव (1991–2021)

1.6 भू-नगरीकरण के प्रमुख कारण

- बेहतर आर्थिक अवसरों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन।
- सड़क और परिवहन बुनियादी ढांचे का विस्तार।
- शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता।

1.7 पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव

- पर्यावरणीय प्रभाव: वन क्षेत्र में कमी, जल संसाधनों पर दबाव, और प्रदूषण में वृद्धि।
- सामाजिक प्रभाव: पारंपरिक ग्रामीण जीवनशैली का ह्रास, आवासीय बस्तियों का अनियोजित विस्तार।

1.8 निष्कर्ष और सिफारिशें

1.8.1 निष्कर्ष

- देहरादून जिले की ग्रामीण बस्तियाँ तीव्र भू-नगरीकरण का अनुभव कर रही हैं।
- भूमि उपयोग में बदलाव ने पर्यावरण और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है।

1.8.2 सिफारिशें

- ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास के लिए नियोजन की आवश्यकता।
- कृषि भूमि और जल संसाधनों के संरक्षण हेतु नीतियाँ।
- शहरीकरण के प्रभावों को कम करने के लिए हरित बुनियादी ढांचे का विकास।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- भारत की जनगणना (1991–2021)
- शर्मा, ए. (2019)। देहरादून में भू-नगरीकरण। भारत भूगोल पत्रिका।
- जोशी, पी. (2020)। ग्रामीण से नगरीय परिवर्तन का विश्लेषण। पर्यावरण अध्ययन।
- लैंडसैट डेटा (1991–2021)
- Gupta, Akhilesh, and Arun Kumar. "Impact of Urbanization on Rural Settlements in the Himalayan Region." *Journal of Rural Development*, vol. 32, no. 4, 2016, pp. 487–502.
- Sharma, Kavita, and Deepak Joshi. "Changing Dynamics of Rural Settlements in Uttarakhand: A Geo-Spatial Analysis." *Indian Journal of Geography and Environment*, vol. 24, 2020, pp. 93–108.

- Thakur, Rajiv. "Urbanization and Environmental Challenges in Dehradun District." *Environment and Urbanization Asia*, vol. 5, no. 2, 2014, pp. 121–136.
- Chand, Mahesh, and Vinay Kumar Puri. *Regional Planning in India*. Allied Publishers, 1983.
- Singh, R. L., and K. N. Singh. *India: A Regional Geography*. National Geographical Society of India, 1978.
- Mitra, A. *Urbanization in India: Patterns and Perspectives*. Concept Publishing Company, 1994.

Author's Declaration

I as an author of the above research paper/article, here by, declare that the content of this paper is prepared by me and if any person having copyright issue or patent or anything otherwise related to the content, I shall always be legally responsible for any issue. For the reason of invisibility of my research paper on the website /amendments /updates, I have resubmitted my paper for publication on the same date. If any data or information given by me is not correct, I shall always be legally responsible. With my whole responsibility legally and formally have intimated the publisher (Publisher) that my paper has been checked by my guide (if any) or expert to make it sure that paper is technically right and there is no unaccepted plagiarism and hentricontane is genuinely mine. If any issue arises related to Plagiarism/ Guide Name/ Educational Qualification /Designation /Address of my university/ college/institution/ Structure or Formatting/ Resubmission /Submission /Copyright /Patent /Submission for any higher degree or Job/Primary Data/Secondary Data Issues. I will be solely/entirely responsible for any legal issues. I have been informed that the most of the data from the website is invisible or shuffled or vanished from the database due to some technical fault or hacking and therefore the process of resubmission is there for the scholars/students who finds trouble in getting their paper on the website. At the time of resubmission of my paper I take all the legal and formal responsibilities, If I hide or do not submit the copy of my original documents (Andhra/Driving License/Any Identity Proof and Photo) in spite of demand from the publisher then my paper maybe rejected or removed from the website anytime and may not be consider for verification. I accept the fact that as the content of this paper and the resubmission legal responsibilities and reasons are only mine then the Publisher (Airo International Journal/Airo National Research Journal) is never responsible. I also declare that if publisher finds Any complication or error or anything hidden or implemented otherwise, my paper maybe removed from the website or the watermark of remark/actuality maybe mentioned on my paper. Even if anything is found illegal publisher may also take legal action against me.

शिल्पी,
डॉ. चंद्र मोहन राजोरिया
